भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4199

26 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन

†4199. श्रीमती डी. के. अरुणाः

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन पर काम कर रही है और यह मिशन पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए, भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन की सुविधा प्रदान करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की घोषणा की है ताकि भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन को सुगम बनाया जा सके। आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा में नेशनल हॉरिज़ान्टल रिफ्रेंस फ्रेम (एनएचआरएफ) और नेशनल वर्टिकल रिफ्रेंस फ्रेम (एनवीआरएफ) से युक्त नेशनल जियोडेटिक भू-गणितीय रिफ्रेंस शामिल है और इसमें ऑर्थोरेक्टीफाइड इमेजरी (ओआरआई) और डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) शामिल हैं, साथ ही जियो-आईसीटी अवसंरचना सभी हितधारकों को बेहतर और दक्ष भू-अभिलेख, सतत शहरी विकास और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बेहतर डिजाइन प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी।

*****